सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 26 JUNE TO 2 JULY 2020 • VOLUME-42 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
No Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

मानसून आते ही केंद्र और पंजाब राज्य के अधिकारियों की खुली पोल

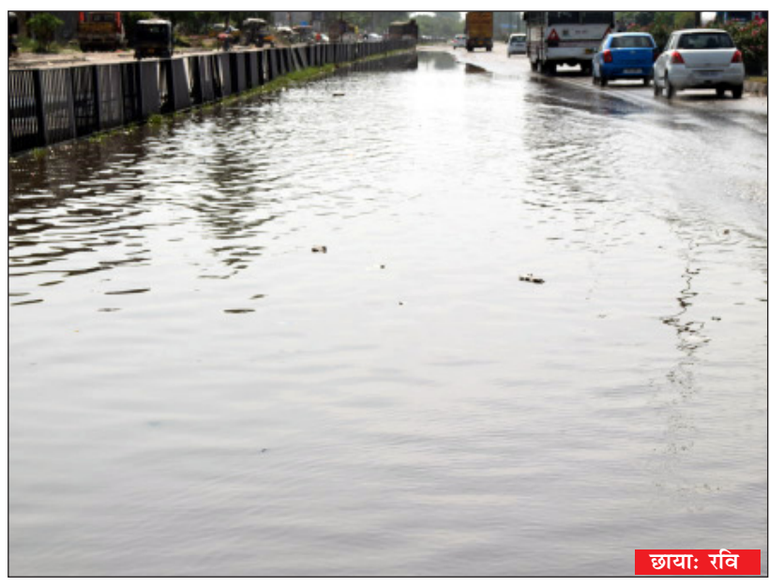

राष्ट्रीय राजमार्ग किसी समुन्द्री तट के साथ सटा हुआ?

नीरज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज। केंद्रीय मंत्री अपने भाषणों में कई बार अपने विभागों की उपलब्धियां संसद में और टी.वी. चैनेलों पर बताते रहते है जिसमें वो हर बार इसी बात पर ज़ोर देते है कि हमने 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण को पूरा किया है और भविष्य में इसको 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनाने का लक्ष्य रखा है।

कोरोना की माहामारी ने जहां देश की अर्थ व्यवस्था को हिला के रख दिया है वहीं इस का प्रभाव निर्माण कार्यों पर भी भारी पड़ा है परंतु केंद्रीय मंत्री ने निर्माण कार्यों को समय सीमा पर पूरा करने के लिए ठेका प्राप्त कंपनियों को कई प्रकार की रियातें प्रदान की है जिसमें कि विभाग द्वारा नोटिफकेशन जारी करके ये आदेश दिया गया है कि ठेकेदारों की जितनी भी सिक्योरिटी के रूप में या बैंक ग्रांटी के रूप में विभाग के पास लंबित पड़ी है उसको जल्द से जल्द अफसर उनको प्रदान करें।

परंतु हैरानीजनक बात ये है कभी भी केंद्रीय मंत्री द्वारा सड़क हादसों में अपनी जान गवा बैठे लोगों को कितना मुआवजा दिया या हाईवे की त्रुटीयां को दूर करने के लिए ठेका प्राप्त कंपनियां जो करोड़ों रुपया रोजाना टोल टैक्स के रूप में आम जनता से वसूला जा रहा है और बदले में सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है और इन सब के लिए जिम्मेवार अधिकारियों को ठेका प्राप्त कंपनियों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? इस पर कभी कोई भाषण नहीं दिया।

जालंधर ब्रीज़ पिछले कई समय से केंद्र और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास कर रहा है परंतु केंद्र और राज्य अधिकारियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला कर आम लोगों को सुविधायों से वंचित रख कर उनको महसूस करवाया जा रहा है कि तुम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गये परंतु हमारे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों से कैसे बचोगे।

इसका उदाहरण आप को राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्ब मल्टीप्लेक्स से लेकर पठानकोट चौंक की तरफ जाते हुए हाईवे की मेन रोड़ की दोनों तरफ से स्लिप रोड़ पर दयनीय हालत देखकर लगेगा कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग किसी समुन्द्री तट के साथ सटा हुआ है। इन सब बातों की विस्तृत जानकारी पिछले दिनों नगर-निगम कमिश्नर करनेश शर्मा, जिलाधीश घनश्याम थोरी को जालंधर ब्रीज के संपादक द्वारा लिखित रूप में दे दी गई है।

हाईवे की त्रुटियों के बारे में विस्तृत जानकारी को लेकर जालंधर ब्रीज के संपादक अतुल शर्मा ने जालंधर जिला के जिलाधीश घनश्याम थोरी व नगर-निगम कमिश्नर करनेश शर्मा के साथ विशेष मुलाकात की गई।

हाईवे अधिकारियों ने हवेली रैस्टोरैंटो के अवैध लगे बोर्डों को हटवाया

नीरज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज। जालंधर पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई दिनों से हवेली रैस्टोरैंट दुआरा विज्ञापन के बोर्डो को हाईवे के नीयमों के विपरीत जा कर सैंटल वर्क पर, डरेन पर, अवैध तरीकों से लगाये गये थे। नैशनल हाईवे के नियमों के अनुसार उसकी जमीन पर किसी भी तरह का विज्ञापन बोर्ड, इत्यादि ऐसी कोई भी चीज नैशनल हाईवे की इश्तहार पालिसी के खिलाफ है और ना ही विभाग इसकी इजाजत देता है ।

इसी लड़ीवार में विभाग की पैट्रोलिंग टीम द्वारा उच्च अधिकारीयों के मिले आदेशों से इन बोर्डों को हटाने के लिए आज और कल डैमोलेशन ड्राईव चलाई गई ओर विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा फोन पर संपर्क साधने पर बताया गया कि ऐसी किसी भी अवैध होडिंग को लगने नहीं देंगे ओर भविष्य में अगर कोई शिकायत आती है तो हम कार्यवाही करेंगे कानून और नियम सब के लिए एक है।

भारत की दो टूक, सीमा पर तनाव, झड़प के लिए चीनी हरकतें जिम्मेदार

सीमा पर चीन ने भारी हथियार जमा किए

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव भारत और चीन के सेनाओं के बीच तनाव जारी है। भारत ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव और गलवान घाटी की हिंसक झड़प के लिए चीन की हरकतें जिम्मेदार हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न समझौतों का पालन नहीं कर रहा है जिससे सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मई की शुरुआत से चीन एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रहा है। साथ ही उसने सीमा के पास हथियारों का जमावड़ा भी लगा रखा है। चीनी सेना ने मई की शुरुआत में गलवान घाटी इलाके में भारतीय सेना की गश्त में बाधा डाली। लेकिन इसे ग्राउंड कमांडरों ने सुलझा लिया था। इसके बाद मई के मध्य में चीन के सैनिकों ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की जिसका भारत ने सैन्य और कूटनीतिक तरीके से विरोध किया।

सहमति का पालन नहीं कर रहा चीन: उन्होंने कहा कि 6 जून को कोर कमांडरों की बैठक में दोनों सेनाओं के बीच एलएसी पर मौजूदा स्थिति से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। लेकिन चीन ने गलवान घाटी में ढांचा खड़ा करने की कोशिश की जिससे 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई।

गलवान इलाके में पीछे हटे चीन के कुछ सैनिक

प्रवक्ता ने कहा कि चीन की हरकतें सीमा पर शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न समझौतों के अनुरूप नहीं है। खासकर 1993 के समझौते में साफ कहा गया है कि दोनों पक्ष एलएसी पर न्यूनतम सैन्य बल रखेंगे। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और मजबूरन भारत को भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी पड़ी है।

भारत, दक्षिणपूर्व एशिया को चीन से खतरा: पॉम्पिओ

वाशिंगटन, (एजेंसी)। एक ओर चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास तनावपूर्ण स्थिति को हवा दे रखी है, तो दूसरी ओर साउथ चाइना सी में भी आक्रामक रवैया अपना रहा है। कोरोना को लेकर भी दुनिया के सामने कड़े तेवर अपना रहा है। चीन की हालिया गतिविधियों के देखते हुए अमेरिका ने उसे इतना बड़ा खतरा करार दिया है कि यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करनी शुरू कर दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने चीन को भारत और दक्षिणपूर्व एशिया के लिए खतरा बताया है और कहा है कि उसकी वजह से अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना घटानी शुरू कर दी है।

शाहपुरकंडी डैम प्रोजैक्ट का कार्य युद्ध स्तर पर जारी - सरकारिया

कोविड पाबंदियों के बावजूद अब तक मेन डैम का 45 प्रतिशत कार्य मुकम्मल किया

चंडीगढ़/ब्यूरो

कोविड -19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के बावजूद शाहपुरकंडी डैम प्रोजैक्ट को समय पर मुकम्मल करने के लिए जल स्रोत विभाग, पंजाब युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और मुख्य डैम का अब तक 45 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

यह जानकारी देते हुए पंजाब के जल स्रोत मंत्री स. सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने बताया कि कोविड -19 को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी विकास कार्य रुक गए थे। कोविड से बचाव सम्बन्धी 'मिशन फतह' के अंतर्गत बताए गए सभी सुरक्षा उपायों को यकीनी बनाते हुए जल स्रोत विभाग ने 29 अप्रैल, 2020 को शाहपुरकंडी डैम प्रोजैक्ट का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया है। अब, इस प्रोजैक्ट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और मेन डैम का 45 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।

शाहपुरकंडी डैम प्रोजैक्ट के जलाशय की भराई साल 2022 के आधे तक शुरू होने की उम्मीद जाहिर करते हुए स. सरकारिया ने बताया कि इस प्रोजैक्ट में अगस्त, 2023 तक बिजली उत्पादन शुरू होने की आशा है। इससे रा%य में सिंचाई प्रणाली और वातावरण समर्थकीय बिजली उत्पादन में और सुधार आएगा।

उन्होंने कहा कि यह माधोपुर हैड वर्कस से शुरू होने वाली नहरी प्रणाली को एकसमान पानी की सप्लाई यकीनी बनाएगा और इस प्रोजैक्ट से पंजाब में तकरीबन 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सिंचाई क्षमता पैदा होने की संभावना है और यू.बी.डी.सी. प्रणाली अधीन इस प्रोजैक्ट से 1.18लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा इस प्रोजैक्ट के मुकम्मल होने पर सालाना 1042 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी।

जिक्रयोग्य है कि रावी नदी पर पठानकोट जिले में रणजीत सागर डैम के 11 किलोमीटर के डाउनस्ट्रीम और माधोपुर हैडवर्कस के 8किलोमीटर अपस्ट्रीम पर शाहपुरकंडी डैम प्रोजैक्ट बनाया जा रहा है। इससे रावी नदी के पानी का पाकिस्तान को बहाव घटेगा और इसका पंजाब और जम्मू-कश्मीर को लाभ होगा।

चीफ इंजीनियर (शाहपुरकंडी डैम प्रोजैक्ट) श्री एस. के. सलूजा ने बताया कि शाहपुरकंडी पावर हाऊस में 206 मेगावॉट बिजली उत्पादन के अलावा यह प्रोजैक्ट डाउनस्ट्रीम बिजली प्रोजेक्टों के लिए पानी की नियमित सप्लाई यकीनी बनाएगा। इस सरहदी इलाके में इस प्रोजैक्ट से पर्यटन क्षमता पैदा होगी और लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने आगे बताया कि पावर हाऊसों के निर्माण कार्यों के लिए टैंडर जल्द ही जारी किये जाएंगे। पीएसपीसीएल ने पावर हाऊसिज के इलैक्ट्रोमकैनिकल सम्बन्धी कार्यों को बी. एच. ई.एल. को सौंप दिया है।

दखल

स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश पर थोपा गया आपातकाल पहला महासंग्राम था जिसमें संपूर्ण देश ने अपनी भूमिका निभाई, परंतु कैसा दुर्भाग्य, नई पीढ़ी से इस इतिहास को छुपाकर रखा गया। इस संघर्ष गाथा को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता से हमने सरकार को दृढ़ता पूर्वक अवगत कराया है। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही बच्चों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

आपातकाल-आजादी की दूसरी लड़ाई

जहां एक ओर कोविड-19 वायरस वैश्विक महामारी के कारण हमारा देश संकट के गंभीर दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन, पाकिस्तान और नेपाल ने हमें चिंतित कर दिया है। आपातकाल समर्थकों के द्वारा दुश्मन देशों के प्रोपेगैंडा ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है लेकिन संतोष की बात है कि देश इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट है व हमारी सेनाएं सीमाओं पर मुंहतोड़ जबाव दे रही हैं। ऐसे में आपातकाल योद्धाओं का कर्तव्य है कि वे देश विरोधी प्रोपेगैंडा करने वालों को बेनकाब कर चीनी सामान का उपयोग न करने तथा इस विषय में जनजागरण करने का संकल्प लें, यह देश और समय की आवश्यकता है। हम भारतवासी सदैव से ही स्वतंत्रता के प्रेमी और उपासक रहे हैं इसलिए जब-जब भी हमारी स्वाधीनता को अपहृत करने के प्रयत्न हुए, हमने उसका प्रतिकार किया है। अनेकबार विदेशी शक्तियों ने हमें पराधीन बनाने की कोशिश की, किंतु हमारे पूर्वजों ने उनके विरुद्ध सतत संघर्ष किया और अंततः विजयी हुए।

स्वतंत्रता की महिमा से मंडित हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में हमारी आजादी के हरण का एक काला अध्याय दर्ज है किंतु उसके साथ ही दूसरी आजादी की हमारी संघर्ष गाथा भी जुड़ी है। वह हमारे आजादी से जीने के संस्कार का एक ज्वलंत उदाहरण है। परंतु वर्तमान की नई पीढ़ी को लोकतंत्र पर आई इस अमावस्या की शायद ही कोई जानकारी होगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 25 जून 1975 में एक ऐसा भी अवसर आया जब एक सत्तासीन व्यक्ति ने, जिनका उनके अपने भ्रष्टाचरण के कारण चुनाव परिणाम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, सत्ता पिपासा को पूरा करने के लिए देशवासियों के सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को तथा सारी संवैधानिक मर्यादाओं को समाप्त कर संपूर्ण देश को आपातकाल की बेड़ी में जकड़ दिया। आपातकाल लगाने के लिए आवश्यक सारे संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करके यह घोषणा की गई थी।

बता दें कि प्रावधानों के तहत आधे से अधिक प्रांत जब मांग करें, नोट भेजें कि कानून व्यवस्था संकट में है और केंद्रीय कैबिनेट सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे तब आपातकाल लगता है किंतु इंदिरा जी और उनके निकटस्थों को भय सता रहा था कि वे कहीं सत्ता से बेदखल ना हो जाएं इसलिए सारे कानून हाथ में लेकर अपनी मनमर्जी से वह किया जो कानून संगत नहीं था। वह तो जब आम निर्वाचन की घोषणा हुई तो उनकी अनेक साजिशें उजागर हुईं। निर्वाचन प्रक्रिया के आरंभ होते-होते इंदिरा जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री बाबू जगजीवन राम ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस छोड़ दी। उस समय उन्होंने खुलासा किया कि देश पर आपातकाल थोपने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में कभी आया ही नहीं, उसे सिर्फ सूचित किया गया और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली महोदय को लिखित सूचना दी गई कि वह प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस प्रकार सारे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के पूरे देश पर तानाशाही का जो तांडव थोप दिया गया उसका नाम था आपातकाल।

कोई अपील नहीं, कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं, न्यायालयों के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए और लाखों निरपराध लोगों की धड़ाधड़ गिरफ्तारी हुई तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहित सभी विरोधी दलों के नेता जिसमें अटल बिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जार्ज फर्नांडीज, कांग्रेस के भी कुछ नेता, 250 से अधिक पत्रकार जेलों में डाल दिए गए। निरपराध नागरिकों के साथ हिंसा का ऐसा तांडव देश ने पहले कभी नहीं देखा था। न्यायपालिका समाप्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों को सुपरसीड करके अपने चुनाव को वैध करा लिया गया, संपूर्ण देश में हाहाकार, जेल के भीतर भी अकेले मप्र में 100 से अधिक लोकतंत्र प्रेमियों की असमय मृत्यु हुई। एक लाख 10 हजार 806 राजनीतिक और सामाजिक नागरिकों को मीसा डीआईआर में बिना मुकदमा चलाए जेलों में निरुद्ध किया गया। इस इतिहास को जानना व परखना लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी के लिए आवश्यक है, नई पीढ़ी को इसे जानने की जरूरत है जिसकी प्रेरणा से भविष्य में लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा जा सके।

देश हित में यह बहुत आवश्यक है ताकि अभिव्यक्ति की आजादी फिर कभी बाधित न हो पाए। 25 एवं 26 जून 2006 को करेली में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें मध्यप्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोकतंत्र सेनानी शामिल हुए थे। तब लोकतंत्र सेनानी संघ को एक राज्यस्तरीय संगठन बना लिया गया था। 26 जून 2015 को भोपाल में आयोजित सम्मेलन में इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। संगठन का परिपूर्ण आकार सभी के सामने है वह इसके केंद्रीय पदाधिकारियों के निरंतर प्रवास और प्रयास का परिणाम है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक के लोकतंत्र सेनानी संगठित हो चुके हैं। लगभग सभी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ चुके इन सेनानियों के उत्साह में आज भी कोई कमी नहीं आई है। देश हित में कुछ भी कर गुजरने को आज भी ये सभी तत्पर हैं। इसलिए संपर्क होते ही हर प्रांत में प्रांतीय संगठन खड़ा हो गया जिनके प्रांतीय सम्मेलन भी आयोजित हो रहे हैं। इन सेनानियों के त्याग और तपस्या को सम्मानित करने का अर्थ अपने गौरवशाली इतिहास को सम्मानित करना है। जो लोग इतिहास को भुलाने के लिए आमादा थे उन्हें संपूर्ण देश नकार चुका है जिन्होंने इसके महत्व को समझा ऐसे कई प्रांत के मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानियों को मानधन सहित चिकित्सा, यातायात आदि की सुविधा मुहैया करके लोकतंत्र के प्रति अपने श्रद्धाभाव का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला महासंग्राम था जिसमें संपूर्ण देश ने भूमिका निभाई, परंतु कैसा दुर्भाग्य, नई पीढ़ी से इस इतिहास को छुपाकर रखा गया। हमें विश्वास है कि शीघ्र ही बच्चों को इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तत्कालीन सरकार ने ही लोकतंत्र को कलंकित किया था, अतः आज की सरकार का यह दायित्व बनता है कि लोकतंत्र पर लगे उस कलंक को मिटाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर इतिहास के साथ इस निमित्त हमें सरकार के प्रभावशाली मंत्रियों का समर्थन मिल रहा है। इसे निर्णायक स्तर तक पहुंचाने के लिए संगठन की ओर से निरंतर प्रयास जारी है। यह सब किया जाना इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे इस संग्राम से वर्तमान तथा आगे आने वाली पीढ़ियां स्वाधीन जीने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने की सतत प्रेरणा ग्रहण कर सकें और दूसरी ओर शासन-प्रशासन में बैठे लोगों की शक्ति का भी विस्मरण न हो।

हम तो सरकार से बस इतना निवेदन कर सकते हैं कि जिस संघर्ष की सीढ़ी चढ़कर आज आप आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं, उस सीढ़ी को, उस इतिहास को महत्व दें और उन इतिहास पुरुषों को सम्मानित करें। पिछले 44 साल में हम लगभग 70 हजार लोकतंत्र सेनानियों को हम खो चुके हैं। रोज देशभर से जिस प्रकार के शोक समाचार मिल रहे हैं, उससे लगता है कि अगले दस साल में इनकी प्रजाति विलुप्ति की कगार तक पहुंच जाएगी। अतः ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय को और अधिक टाला नहीं जाना चाहिए।

विचार

भारतीय कूटनीति की कड़ी परीक्षा

भारतीय कूटनीति के अतीत को देखते हुए लद्दाख के मामले में सफलता को लेकर संदेह करने का कारण नहीं बनता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मौजूदा दौर भारतीय कूटनीति की कुछ ज्यादा ही कड़ी परीक्षा ले रहा है। मौजूदा स्थिति टेंशन वाली जो है।

पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनातनी खत्म करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बीच चीन की नापाक हरकत फिर सामने आई है। एलएसी की गलवां घाटी में 15-16 जून की दरम्यानी रात हुई झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सेना के जो सैन्य ढांचे उखाड़ फेंके थे, वहां पर उसने पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 के पास चीन ने एक निगरानी पोस्ट बना ली है। यहां तक कि चीन दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में पेट्रोलिंग प्वाइंट 10 से 13 तक भारतीय सैनिकों के गश्त करने में रुकावट भी खड़ा कर रहा है। हालांकि, भारत ने चीनी सेना के किसी भी उकसावे की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी के अग्रिम मोर्चे पर बुधवार को पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने रक्षा तैयारियों का जायजा लेकर जवानों को पूरी मुस्तैदी और हौसले के साथ किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है।

खबर यह भी है कि चीन की सेना ने चार मई से सैन्य ढांचा बनाना शुरू किया और बड़ी संख्या में तोपें, हथियारबंद रेजिमेंट और रक्षा बैटरी के जमावड़े के साथ-साथ 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी है। पैंगोंग त्सो झील के साथ लगे फिंगर इलाके में भी चीन ने सेना और सैन्य ढांचे बनाने के काम में तेजी ला दी है। भारतीय पक्ष फिंगर 8 तक दावा जताता रहा है, पर चीन की सेना गलवां घाटी में झड़प के दौरान से ही फिंगर 4 से आगे जाने पर भारतीय सेना के गश्ती दल का रास्ता रोक रही है। फिंगर इलाके में चीन की सेना नए क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की आक्रामक कोशिश कर रही है। इसके साथ ही चीन एक साजिश और रच रहा है। पता चला है कि कूटनीति और रणनीति में भारत से मात खा रहा चीन जैविक हमला कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय दबाव में वह सीधे तौर पर हमला न कर भारत विरोधी देशों या आतंकियों के माध्यम से भी ऐसा करा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका पहले ही प्रश्नों के घेरे में है।

भारत वर्तमान में पड़ोसी मुल्कों की भूमिका से अशांत है। कूटनीतिक और सैन्य घेराबंदी से चीन बौखलाया है। सीमा पर पाक भी रह रह कर गोलाबारी कर रहा है। नेपाल का रवैया भी ठीक नहीं है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर चीन जैविक हमले जैसी कायराना हरकत कर सकता है। इन सबके बाद भी मौजूदा संदर्भों में सबसे अच्छी बात यही है कि सीमा पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण झड़प के बाद भी दोनों देशों में संवाद जारी है। इस बात का अहसास उसे जल्द से जल्द कराना भारत की कूटनीतिक कामयाबी की कसौटी है। भारतीय कूटनीति के शानदार अतीत को देखते हुए इस मामले में उसकी सफलता को लेकर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मौजूदा दौर भारतीय कूटनीति की कुछ ज्यादा ही कड़ी परीक्षा ले रहा है। मगर भारत इसमें सफल होकर दिखाएगा।

सरकार के प्रति किसान का विश्वास

मार्च माह के अंतिम सप्ताह में मध्यप्रदेश की सत्ता में सकारात्मक बदलाव हुआ, जिसके सकारात्मक परिणाम अल्प समय में ही दिखने लगे हैं। कोरोना संकट के दौरान भी प्रदेश की नई भाजपा सरकार ने हर वर्ग को खुशहाली दी और नई योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को हरसंभव मदद पहुंचाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मागदर्शन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मप्र सरकार हर परिस्थिति में प्रदेशवासियों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। मध्यप्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जिसने दावा किया और वचन दिया कि वह किसानों के साथ है व किसान हितैषी दरअसल वह किसान विरोधी और अपने हर वचन से मुकरने वाली सरकार साबित हुई। पिछली सरकार की नीयत साफ और स्पष्ट न होने की वजह से उनके वचन झूठे साबित हुए। न किसानों का कर्ज माफ हुआ, न प्रदेश के किसानों को सुविधाएं मिलीं और न ही पिछली सरकार द्वारा फसल बीमा का प्रीमियम जमा किया गया।

हर मोर्चे पर, हर वर्ग को पिछली सरकार ने केवल छला है, झूठा आश्वासन दिया और प्रदेशवासियों को गुमराह करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होते ही प्रदेश के विकास का रुका हुआ पहिया फिर से गतिमान हुआ। अब सभी वर्ग को सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। जिसका सुपरिणाम है कि प्रदेशवासियों खासकर मध्यप्रदेश के किसानों का विश्वास भी हमारी सरकार के प्रति बढ़ा है। भाजपा द्वारा किसानों को लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौरान कई सुविधाएं प्रदान की गईं, जिसका नतीजा आज देश के सामने है। हमारे अन्नदाता ने कीर्तिमान बनाते हुए गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश का शीर्ष राज्य बना दिया है। सही मायने में किसान हितैषी प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में आवश्यक संशोधन किया गया।

जिसके अनुसार निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना, कृषकों से मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर, निर्यातकों, विक्रेता व अंतिम उपयोगकर्ताओं को सीधे खरीदने का प्रावधान, पूरे प्रदेश में एक ही लायसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने और ई-ट्रेडिंग की व्यवस्था जैसे प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन फसलों मूंग एवं उड़द की बिक्री के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गईं। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए। पिछले वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या 3 हजार 545 थी, जिसको बढ़ाकर 4 हजार 529 किया गया। किसान को उपार्जन केंद्र से, मंडी द्वारा अधिकृत खरीद केंद्रों से और मंडी में पंजीकृत व्यापारी को सौदा पत्रक के माध्यम से अपनी फसल बेचने की सुविधा दी गयी, लेकिन किसानों ने सरकार की व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए उपार्जन केंद्र का विकल्प बहुतायत में चुना। इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उनमें से लगभग 82 प्रतिशत गेहूं बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40 प्रतिशत था, जो बढ़कर इस बार 84 प्रतिशत हो गया है। गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया में स्व-सहायता समूह की भागीदारी दर्ज कराने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना, प्रदेश के 6 जिलों में 16 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मध्यप्रदेश में लगभग 15 लाख 93 हजार किसानों से एक करोड़ 29 लाख 28 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्यप्रदेश में गेहूं उपार्जन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में 73.69 लाख गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था।

पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों व भंडारण की व्यवस्था की गई। 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। राज्य सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित की गई। लगभग 16 लाख किसानों के खातों में 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। कुल उपार्जित गेहूं का लगभग 95 प्रतिशत परिवहन कर सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है। गत वर्ष किसानों से चने की खरीदी अधिकतम 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आधार पर की गई थी, प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिये चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल करने का निर्णय लिया। इससे किसान अधिक उपज बेच पा रहे हैं, प्रदेश में पंजीकृत 5 लाख 30 हजार किसानों को इसका फायदा मिलेगा। चने के विक्रय से लगभग 325 करोड़ रुपए और सरसों के विक्रय से लगभग 146 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ किसानों को होगा। प्रदेश में चना, सरसों एवं मसूर खरीदी भी हुई।

भाजपा की सत्ता में वापसी होते ही प्रदेश के विकास का रुका हुआ पहिया फिर से गतिमान हुआ। अब सभी वर्गों को सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। जिसका सुपरिणाम है कि प्रदेशवासियों खासकर मध्यप्रदेश के किसानों का विश्वास भी हमारी सरकार के प्रति बढ़ा है। हमारे अन्नदाता ने कीर्तिमान बनाते हुए गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश का शीर्ष राज्य बना दिया है।

प्रदेश में चना उपार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के लगभग 700 उपार्जन केंद्रों पर यह खरीदी की गई है। अब तक 2 लाख 88 हजार से अधिक किसानों के खाते में 2762 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मध्यप्रदेश में चना, मसूर, सरसों की प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन अधिकतम उपार्जन सीमा प्रति व्यक्ति 40 क्विंटल को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान चना, मसूर और सरसों की जितनी उपज है, उसे लेकर मंडी में आ सकते हैं और विक्रय कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 71.05 लाख हितग्राही हैं। इन किसानों के लिये 2000 रुपए के मान से कुल 1500 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के खरीफ एवं रबी फसलों के लिए फसल बीमा राशि के रूप में 2200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया था, जिससे किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल सका। प्रदेश के किसानों को 2900 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि के भुगतान का निर्णय लिया गया एवं प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मार्च 2020 में ही बीमा कंपनियों को प्रीमियम राशि के रूप में 2200 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए।

शून्य ब्याज दर पर किसानों को ऋण दिए जाने की योजना का वर्ष 2019-20 के लिए क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी प्रदेश के किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया। विगत दो माह की अल्प अवधि में प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में कई सुनियोजित कार्य किए गए और किसानों के हित में दूरगामी निर्णय लिए गए।

ट्विटर

भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि वह अपनी हद में रहे और पहले की स्थिति को बहाल करे। अब भारत लद्दाख मामले में कतई पीछे हटने वाला नहीं है।

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री

लद्दाख के मोर्चे पर भारत की कूटनीति शानदार है। मगर भविष्य में अगर चीन को काबू में रखना है तो भारत को पाक और नेपाल पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ

सत्यार्थ

क्षमाशीलता का प्रभाव

जापान में कागावा नामक एक संत रहते थे। लोग उन्हें जापान का गांधी कहते थे। वे गांधीजी की ही तरह अत्यंत सादगी से रहते थे। वे लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और सभी उनका सम्मान करते थे। मगर एक व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता था। वह किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी वजह से सभी उससे दूर ही रहते थे। जब उसने देखा कि चारों तरफ कागावा की प्रशंसा होती है और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं तो उसने तय किया कि रात को सोते समय वह

उनकी गर्दन तलवार से काट देगा। वह कागावा के घर पहुंचा। धीरे से दरवाजा खोलकर कागावा के कक्ष में जाकर खड़ा हो गया। संत को सोते देखकर उसने जैसे ही तलवार उठाई, कागावा की नींद खुल गई। वह डर गया कि अब कागावा शोर मचाएंगे और उनके सभी शिष्यों के यहां आने पर उसकी योजना पर पानी फिर जाएगा। लेकिन कागावा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की- हे प्रभु, मेरे इस भाई को सद्बुद्धि दो, इसका कल्याण करो। उस व्यक्ति ने जब यह देखा तो उसे बहुत ग्लानि हुई। वह तो संत को मारने आया था और संत उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर उसके लिए न क्रोध है, न घृणा, बस प्रेम ही प्रेम है और क्षमा का उदात्त भाव। उसने तलवार फेंक दी व कागावा के चरणों में गिर पड़ा। कागावा ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोले-भाई, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। प्रभु तुम्हें क्षमा करें और सत्कर्म करने की शक्ति दें। उसी समय से वह व्यक्ति सदाचारी बन गया। सच ही कहा जाता है कि सच्चे संत के प्रभाव से क्रूर से क्रूर व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है।

मारुति सुजुकी की S-PRESSO सीएनजी लॉन्च

31.2 किमी की माइलेज

मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार (22 जून) को अपने मिनी एसयूवी एस-प्रेसो के एस-सीएनजी वैरिएंट को लॉन्च कर दिया है और यह बीएस6 इंजन के साथ उतारा गया है। देश में अपने ग्रीन कारों के सेगमेंट को बढ़ाने के मद्देनजर कंपनी इसमें सीएनजी और बीएस6 इंजन को साथ लेकर आई है। पहले से ही कार में फिट एस-सीएनजी वैरिएंट में सुरक्षा पर जोर दिया गया है। वहीं, इसकी परफॉर्मेंस और सुविधा में भी काफी सुधार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मारुति देश की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने दस साल पहले फैक्टरी फिटेड सीएनजी कार को पेश किया था और आज भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली सबसे अधिक ग्रीन कारें (पर्यावरण के अनुकूल) इसी कंपनी की हैं। 2019-2020 में कंपनी ने ईको फ्रेंडली सीएनजी श्रेणी में अब तक सबसे अधिक कारों की बिक्री की। कंपनी ने पूरे देशभर में 106,443 फैक्टरी फिटेड सीएनजी कार को बेचा। ईको फ्रेंडली को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 सालों में कंपनी के सीएनजी कारों की बिक्री के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में 15.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

एस-सीएनजी फिटेड के साथ बीएस6 इंजन वाली यह कार एक किग्रा (सीएनजी) में 31.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसकी टैंक क्षमता 55 लीटर (वॉटर फीलिंग कैपेसिटी) है।

कार को चार वैरिएंट में उतारा गया है	दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत
S-PRESSO BS6 LXI CNG	484,000 रुपए
S-PRESSO BS6 LXI (O) CNG	490,000 रुपए
S-PRESSO BS6 VXI CNG	507,500 रुपए
S-PRESSO BS6 VXI (O) CNG	513,500 रुपए

9.12 लाख रु. कीमत का टोयोटा यारिस फ्लीट वैरिएंट लॉन्च

टोयोटा मोटर ने बुधवार को बताया कि यारिस सेडान अब गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (त्द्गरू) पर भी उपलब्ध है। त्द्गरूसरकारी संगठनों, विभागों और विभिन्न [illegible] के लिए डेडिकेटेड गुड्स एंड सर्विसेस ई-कॉमर्स वेबसाइट है। यारिस का फ्लीट वैरिएंट, J(MT) पेट्रोल वैरिएंट पर बेस्ड है, जिसकी कीमत 9.12 लाख रुपए (डिलीवरी चार्ज सहित)। हालांकि, फ्लीट वैरिएंट स्टैंडर्ड J-वैरिएंट की तुलान में लगभग 1.96 लाख रुपए सस्ता है।

फ्लीट वैरिएंट का इंटीरियर और एक्सटीरियर

कंपनी के मुताबिक, फ्लीट मार्केट के लिए उपलब्ध यारिस सात एयरबैग, एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर और रियर पार्किंग सेंसर से लैस है। वहीं, बाहर की तरफ यारिस के इस संस्करण में 15 इंच अलॉय व्हील्स और हलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। फिलहाल यह मुख्य रूप से एक सुपर व्हाइट कलर में उपलब्ध है जबकि रिक्वेस्ट के आधार पर अन्य रंगो में भी इसकी डिवीलरी की जाएगी। अंदर की तरफ फ्लीट-स्पेक यारिस में डुअल-टोन इंटररियर्स मिलता है। इसमें एडजस्टेबल फ्रंट और रियर हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, पावर एडजस्टेबल विंग मिरर, पावर विंडो, मैनुअल एसी जैसे फीचर्स है और रियर चार्जिंग आउटलेट मिलने की भी उम्मीद हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 80kph स्पीड लिमिटर मिल सकता है जो कैब्स नॉर्म्स के लिए जरूरी है।

स्टैंडर्ड-J वैरिएंट जैसे ही मिलेगा इंजन

इंजन की बात करे तो यारिस का फ्लीट वैरिएंट स्टैंडर्ड-छ्व वैरिएंट के समान है। इसमें 107hp/140Nm टॉर्क जनरेट करने वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

Hero Electric का नया ऑफर, ई-स्कूटर पर 4 हजार रुपए तक की छूट

इलेक्ट्रिक टू-वीलर निर्माता Hero Electric एक नई स्कीम लेकर आई है, जिससे तहत कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर 4 हजार रुपए तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा फ्री में कंपनी का 'Glyde e-scoot' और Hero Optima लिथियम-आयन इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतने का भी मौका है। कंपनी ने इस नई रेफरल स्कीम को 'Be a Bike Buddy' नाम दिया है।

हीरो इलेक्ट्रिक की नई स्कीम के तहत कंपनी के ई-स्कूटर्स पर 2 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही अगर आप किसी मौजूदा हीरो इलेक्ट्रिक कस्टमर का रेफरेंस देंगे, तो दो हजार रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसका मतलब नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीदारी पर कुल 4 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा, इस रेफरल स्कीम के तहत आने वाले हर 50वें ग्राहक को फ्री में 'Glyde e-scoot' मिलेगा, जिसके लिए कंपनी ने कुछ नियम तय किए हैं।

हीरो इलेक्ट्रिक की नई स्कीम

दूसरी ओर, नए ग्राहक को रेफरेंस देने वाले हीरो इलेक्ट्रिक के मौजूदा कस्टमर को कंपनी 1 हजार रुपये का डिस्काउंट कूपन देगी। साथ ही ऐसे ग्राहकों को फ्री में हीरो ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतने का भी मौका मिलेगा। हीरो इलेक्ट्रिक की यह रेफरल स्कीम 15 जुलाई तक के लिए है।

होम डिलिवरी और यूज करके स्कूटर वापस करने की सुविधा

कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान हीरो इलेक्ट्रिक ने अपना ऑनलाइन सेल्स प्लैटफॉर्म पेश किया, जहां कंपनी के लिथियम-आयन बैटरी वाले स्कूटर्स पर 5,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर किया था। ऑनलाइन सेल्स के तहत कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की होम डिलिवरी, डोर स्टेप सर्विस और तीन दिन तक यूज करके स्कूटर वापस करने जैसी सुविधाएं देती है।

Honda Grazia 125 BS6 स्कूटर अपडेटेड इंजन और फीचर्स के साथ लॉन्च

Honda Motorcycle and Scooter India Pvt. Ltd. (HMSI), होंडा मोटरसाइकल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने बुधवार को ऑल-न्यू Grazia 125 (ग्राजिया 125) BS6 स्कूटर लॉन्च किया। यह अपडेटेड स्कूटर दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। अप्रैल में नए क्र्ञ्6 ईंधन उत्सर्जन मानक लागू होने के बाद होंडा ने इस स्कूटर को वेबसाइट से हटा दिया था। अब कंपनी ने बिलकुल नए अवतार में पेश किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को सालाना अपडेट के साथ ही कुछ अहम अपडेट दिए हैं। इस स्कूटर के एक्सटीरियर और स्टाइलिंग में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा इसमें अपडेटेड इंजन के साथ-साथ कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं।

फीचर्स: 2020 Honda Grazia स्कूटर पर दिए गए नए फीचर्स में एलईडी डीसी हेडलैंप, इंजन स्टार्ट / स्टॉप स्विच, न्यू इंटीग्रेटेड हेडलैम्प बीम और पासिंग स्विच शामिल हैं, जो अनिवार्य रूप से दोनों को नियंत्रित करने के लिए एक सिंगल स्विच है। सीट अनलॉक करने के लिए और बाहरी फ्यूल लिड (ढक्कन) को खोलने के लिए एक नया मल्टी-फंक्शन स्विच दिया गया है। इस स्कूटर में टेलिस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है।

होंडा कार्स इंडिया ने नई 5th जेनरेशन होंडा सिटी के लिए शुरू की प्री.लॉन्च बुकिंग

- ग्राहक नए मॉडल को ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म 'होंडा फ्रॉम होम' और पूरे भारत में मौजूद डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं
- 5th जेनरेशन मॉडल -अपने सेगमेंट में सबसे लंबी और चौड़ी है
- एलेक्सा रिमोट क्षमता वाली भारत की पहली कनेक्टेड कार
- आसियान एन-कैप 5 स्टार रेटिंग के बराबर
- यह कार सेगमेंट में पहली बार पेश किए गए कई फीचर्स के साथ आती है

भारत में प्रीमियम कारों की अग्रणी निर्माता कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ;[illegible]HCIL ने आज से अपनी सबसे बहुप्रतीक्षित ऑल न्यू 5th जेनरेशन होंडा सिटी के लिए प्री.लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक देश भर में HCILअधिकृत डीलरशिप नेटवर्क के साथ हीए होंडा के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म 'होंडा फ्रॉम होम' के माध्यम से अपने घर पर आराम के साथ अपनी पसंदीदा सेडान बुक कर सकते हैं। अपनी शुरुआत के बाद से हीए होंडा सिटी भारत की सबसे पसंदीदा सेडान रही हैए और अब इसके 5thजेनरेशन अवतार को जुलाई के मध्य में लॉन्च किया जाएगा।

ऑल न्यू होंडा सिटी के बारे में बात करते हुए श्री राजेश गोयल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टरए मार्केटिंग एवं सेल्सए होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने कहा होंडा सिटी ने हमारे ग्राहकों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार अपनी प्रत्येक जेनरेशन के साथ खुद को और बेहतर बनाया है। हमारे ग्राहकों को ऑल न्यू 5th जनरेशन होंडा सिटी के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार है। मॉडल के प्रति ग्राहकों के उत्साह और निरंतर प्यार को ध्यान में रखते हुएए हम ऑल न्यू होंडा सिटी के लिए प्री.लॉन्च बुकिंग शुरू करने की घोषणा करते हुए बेहद खुश हैं। नई कार की बिक्री अगले महीने से शुरू की जाएगी। हमारे सम्मानित ग्राहकों को सबसे बेहतर प्रदान करने के वादे के साथ सिटी की बेहतरीन विरासत और लोकप्रियता को आगे ले जाने के उद्देश्य से सभी नए मॉडल को विकसित किया गया है। हमें उम्मीद है कि हमारे ग्राहकों से ऑल न्यू सिटी को उसकी पिछली जेनरेशन की तरह ही बहुत प्यार मिलेगा।

देश में सेडान सेगमेंट को स्थापित करने वालीए होंडा सिटी की प्रत्येक जेनरेशन ने डिजाइनए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता के मामले में नए मुकाम स्थापित किए हैंए जो इसे उच्च विश्वसनीयता और निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं।

ऑल न्यू 5th जेनरेशन होंडा सिटी के बारे में:ऑल न्यू सिटी एक विशाल और आरामदायक केबिन के वादे के साथए इस सेगमेंट में सबसे लंबी और चौड़ी सेडान है। 5जी जनरेशन पेट्रोल मॉडल में वीटीसी के साथ ऑल न्यू 1.5 लीटर i-VTE DOHC इंजन दिया गया है और डीजल में रिफाइंड 1.5 लीटर -VTEC इंजन है। ये दोनों इंजन ठे.6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप हैं जो दमदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट ईंधन दक्षता की पेशकश करते हैं। ऑल न्यू होंडा सिटी एलेक्सा रिमोट क्षमता के साथ भारत की पहली कनेक्टेड कार है। यह टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट के साथ नेक्स्ट जेनरेशन होंडा कनेक्ट से लैस है। उन्नत हल्के वजन उच्च कठोरता और टक्कर सुरक्षित संरचना के साथ नया डिज़ाइन किया गया प्लेटफॉर्म आसियान एन.कैप 5.स्टार रेटिंग के बराबर बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में पहली बार होंडा में सुपर हाई फॉर्मेबिलिटी 980 एमपीए ग्रेड स्टील के उपयोग के साथ अल्ट्रा हाई टेन्सिल स्टील का उपयोग किया गया हैए साथ ही अन्य उन्नत उच्च शक्ति वाले स्टील ने नए मॉडल को और मजबूत बनाया है और वजन में कमी लाई है।

यह कार इस सेगमेंट में पहली बार पेश किए गए कई फीचर्स से लैस है जैसे फुल एलईडी हैडलैंप्स zशेप रैप-अराउंड एलईडी टेल लैम्पए 17.7 सेमी एचडी फुल कलर टीएफटी मीटर के साथ जी. मीटरए लेन वॉच कैमराए एजाइल हैंडलिंग असिस्ट; (एएचए) के साथ व्हीकल स्टैबिलिटी असिस्ट (वीएसए) आदि। नई होंडा सिटी अत्याधुनिक उपकरण जैसे 20.3 सेमी एडवांस टचस्क्रीन डिस्प्ले ऑडियोए एंड्रॉइड ऑटोए एप्पल कारप्ले और वेबलिंक के साथ आसान स्मार्टफोन कनेक्टिविटीए वन.टच इलेक्ट्रिक सनरूफ भी प्रदान करती है।

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के बारे में

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) भारत में प्रीमियम कारों की एक प्रमुख निर्माता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1995 में भारतीय ग्राहकों को होंडा की नवीनतम यात्री कार मॉडल और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ की गई थी।
एचसीआईएल के पास ग्रेटर नोएडा यूपी और तपुकरा जिला अलवर राजस्थान में दो अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयां हैं। कंपनी की उत्पाद श्रेणी में होंडा जैज होंडा अमेज होंडा डब्ल्यूआर.वीए होंडा सिटी होंडा सिविक और होंडा सीआर.वी शामिल हैं। इनका निर्माण भारत में ही किया जाता है। होंडा के मॉडलों में स्थायित्व विश्वसनीयता और ईंधन-दक्षता के अपने स्थापित गुणों के अलावा उन्नत डिजाइन और प्रौद्योगिकी का समावेश होता है।

अपने वाहन को सैनिटाइज करने की युक्तियों के साथ रहें सुरक्षित

फोर्ड का हर वाहन सर्वोच्च मापदंडों का पालन करता है। इन वाहनों के स्लीक डिजाइन, उन्नत सेफ्टी व ड्राइवर असिस्ट टेक्नॉलॉजी से आपको पूरी सुरक्षा तो मिलती है, पर वायरस या महामारी से आपका बचाव नहीं हो पाता।

भारत में लॉक डाउन प्रतिबंधों को हटाए जाने पर शहरों में आम जन जीवन शुरू हो रहा है और ऐसे में लोग अपने वाहनों को लेकर सड़क पर अवश्य निकलेंगे। घर के बाहर जाना अभी भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन यदि आपका अपनी कार लेकर निकलना बहुत जरूरी है, तो फिर सड़क पर निकलने से पहले कार को क्लीन, सैनिटाइज व डिसइन्फेक्ट करने के बारे में जान लें, ताकि आप सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकें।

क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन व डिसइन्फेक्शन के बीच का अंतर जानें

क्लीनिंग में साबुन व पानी का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से कीटाणु तो दूर हो जाते हैं, लेकिन पानी कीटाणुओं का खत म नहीं करता। सैनिटाइजेशन से कीटाणु कम किए जा सकते हैं और बैक्टीरिया खत्म, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। डिसइन्फेक्शन में कैमिकल्स द्वारा बैक्टीरिया, वायरस एवं फंगाई को मारा जाता है, जिससे क्लीनिंग व सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत हो जाती है।

इनके लिए किन चीजों का उपयोग करें

अपने वाहन में इंटीरियर के लिए डिसइन्फेक्टिंग स्प्रे का उपयोग करें। घर में इस्तेमाल किए जाने वाली क्लीनिंग उत्पाद, जैसे ब्लीच, एसिटोन, क्लोरीन और अमोनिया आपके वाहन के इंटीरियर पेंट को क्षति पहुंचाते हैं। वाहन को अच्छी तरह से डिसइन्फेक्ट करने के लिए डिसइन्फेक्टैंट जर्म फॉगर खरीदें

इनका उपयोग कैसे करें

डिटेलिंग उत्पादों से क्लीनिंग करने के दौरान डैशबोर्ड या अन्य सतहों पर उन्हें सीधे स्प्रे न करें। पहले उन्हें माइक्रोफाइबर कपड़े से स्प्रे करें और फिर उसे सतह पर लगाएं। ऐसा करने के बाद क्विक वैक्यूम की मदद से फैब्रिक सीट एवं हेडलाइनर की धूल साफ कर दें। यदि आपके पास शैंपू एवं वेट वैक्यूम है, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। बाहर की सतह, खासकर दरवाजों के हैंडल को समय-समय पर क्विक वॉश करें।

कार लेदर को कैसे साफ करें?

स्टीयरिंग व्हील के पिछले हिस्से में अपनी पसंद का उत्पाद लगाकर देखें और उसके परिणामों का इंतजार करें। ध्यार रहे आपके द्वारा चुने गए उत्पाद में ब्लीच, एसिटोन, क्लोरीन और अमोनिया न हो। यदि यह उत्पाद कोई दाग नहीं छोड़ता है या फिर कार लेदर का रंग नहीं उड़ाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कार के अन्य हिस्सों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इस उत्पाद को भी आप किसी भी सतह पर सीधे स्प्रे न करें, बल्कि एक साफ माईक्रो-फाईबर कपड़े पर स्प्रे करके उसका उपयोग करें।

डिसइंफेक्टिंग

अब आप अपने वाहन को डिसइन्फेक्ट करने लिए तैयार हैं। कठोर सतहों, जैसे प्लास्टिक बटन एवं नॉब्स आदि को ब्लीच-फ्री डिसइन्फैक्टैंट वाईप से साफ किया जा सकता है या फिर आप माईक्रोफाईबर कपड़े पर डिसइन्फैक्टेंट स्प्रे लगाकर भी साफ कर सकते हैं। आप अपनी कार की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन का इस्तेमाल समय-समय पर करते हैं, फिर चाहे वह इन्फोटेनमेंट टच स्क्रीन हो या फिर कोई अन्य, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनिक जीचों की सफाई के लिए निर्मित नॉन टॉक्सिक डिवाईस क्लीनिंग वाईप का इस्तेमाल करें।

किन सतहों व चीजों की सफाई करनी है

- की/की एफओबी
- एक्सटीरियर डोर हैंडल
- इंटीरियर डोर हैंडल
- लॉक एवं अनलॉक बटन और इंटीरियर डोर रिलीज
- सीटबेल्ट एवं सीटबेल्ट बटन। इसमें रिलीज बटन को भी शामिल करें।
- पुश-टू-स्टार्ट बटन, या इग्निशन का क्षेत्र
- रियर व्यू मिरर, एवं ऑटोमैटिक साईड मिरर बटन्स
- एचवीएससी (HVAC) (हीटिंग, वैंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग) बटन
- रेडियो बटन और नॉब्स या इन्फोटेनमेंट टच स्क्रीन
- गिर सलेक्टर
- पार्किंग ब्रेक लीवर
- स्टीयरिंग व्हील और व्हील माउंटेड बटन्स
- सिग्नल एवं वाईपर स्टाक
- हेडलाईट नॉब्स
- सेंटर कॉन्सोल एवं कप होल्डर्स

इन हिस्सों को भी डिसइन्फेक्ट करें

- विडों बटन्स
- ग्लोव कंपार्टमेंट सिस्टम (टीएमएस) (TMS) रोटरी नॉब
- ग्लोव कंपार्टमैंट हैंडल
- टेगलेट/हैच रिलीज एवं पॉवर क्लोज बटन
- पॉवर फोल्डिंग थर्ड रो बटन्स
- फ्यूल कैप

कार को पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट करने के बाद आप साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह धोना च भूलें। व्यक्तिगत हाईजीन की इस आदत का कोविड-19 की महामारी खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए।

यदि आपको अपनी फोर्ड कार की सर्विस एवं मेंटेनेंस क लिए किस अन्य सहायता की जरूरत है, तो डायल-ए-फोर्ड अभियान आपको सुरिक्षत व सुविधा प्रदान करेगा। आपको सर्विसिंग के लिए 1800-419-3000 पर डायल करना होगा जिसके बाद एक फोर्ड टेक्निशियन आपके घर आकर आपकी कार ले जाएगा। सर्विस किए जाने के बाद कार आपके घर पर सुरक्षित पहुंचा दी जाएगी। इस सेवा का भुगतान आप ऑनलाईन कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं होगा। यह बहुत आसान है

क्या आप अब प्रस्ताव से भाग रहे हो ? क्या आपने प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया था ?

कैप्टन ने सुखबीर से पूछा : शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष स्पष्ट तौर पर जवाब दे - क्या केंद्र सरकार कृषि में दखल देने का हक रखती है?

सुखबीर बादल को दोगली बातें करना बंद करने के लिए कहा, सर्वदलीय बैठक के दौरान उसके बयान रिकार्ड का हिस्सा

चंडीगढ़/ब्यूरो

कृषि क्षेत्र संबधी केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए ऑर्डीनैंसों पर बीते दिन हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पास किये गए प्रस्ताव के मुद्दे पर दोगली बोली बोलने के लिए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पर बरसते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज सुखबीर बादल को चुनौती दी कि वह स्पष्ट शब्दों में यह बयान जारी करे कि उनकी पार्टी सशर्त भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती।

मुख्यमंत्री ने अकाली दल के अध्यक्ष को पूछा, ''क्या आप प्रस्ताव के विरोधी हो या नहीं हो? क्या आप प्रस्ताव के हक में पूरी तरह खड़े हो या शर्तों के अंतर्गत? आखिरी तौर पर क्या आप इस तथ्य से सहमत हो या नहीं कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र को इसमें दखल नहीं देना चाहिए।'' मुख्यमंत्री ने बीते दिन बैठक के अंत में कहा कि अकाली दल के प्रमुख को यही स्पष्ट सवाल किये थे।

बैठक के दौरान विचार-विमर्श संबंधी अकालियों और सुखबीर के झूठे दावों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दिन हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पास किये प्रस्ताव के तीन नुक्तों में से दो नुक्तों पर अकाली दल के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि बैठक के उपरांत जारी किये सरकारी बयान के द्वारा इस पक्ष को सही और निष्पक्ष तौर पर बताया गया और झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल सकते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मसले की सच्चाई यह है कि भाजपा ने बीते कल की वोटिंग के समय प्रस्ताव का पूरा विरोध किया जबकि सुखबीर ने शुरुआत में सीधा समर्थन करने से बचते हुए उनको दो बार यह स्पष्ट करने के लिए रोका कि ''हम यह लिखित रूप में भी भेजेंगे.. कि आपके दो संकल्प.. न्यूनतम समर्थन मूल्य और पक्ष स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बैठक.. .. हम सर्वदलीय प्रस्ताव पर आपके साथ हैं.. .. इस पर क्या यह संघीय ढांचे के उल्लंघन संबंधी कानूनी राय चहेंगे।'' कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने याद करवाया कि वह यह कहने तक गए कि यदि ऑर्डीनैंस संघीय ढांचे की भावना के उलट पाए जाते हैं तो,'' हम इस पर भी आपके साथ हैं।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भी बढ़कर, सुखबीर द्वारा भाजपा की तरह न नहीं की गई जब उन्होंने (कैप्टन अमरिन्दर सिंह) यह कहते हुए बात खत्म की, ''भाजपा-शिरोमणि अकाली दल आंशिक तौर पर प्रस्ताव के हक में हैं आंशिक तौर पर विरोध में और उनके ऐतराज दर्ज किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सब रिकार्ड में दर्ज है जिससे अकाली बैठक की वीडियों के चुनिंदे हिस्से लीक करके आसानी से बच नहीं सकते।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि अकाली अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में राजनैतिक संकट में फंस गए हैं, जिसकी खातिर उनको जरूरत है केंद्रीय सत्ता हिस्सेदारी में अस्तित्व बनाए रखने के लिए भाजपा का समर्थन करने की और पंजाब में पार्टी वोट बैंक बचाने की। उन्होंने साथ ही कहा कि ''यह लगता है कि सुखबीर प्रस्ताव के लिए अपनी शर्तों के साथ किया गया समर्थन वापस लेने के लिए भाजपा में अपने राजनैतिक अकाओं के दबाव में है परन्तु ऐसा जोरदार तरीके से करने की स्थिति में नहीं क्योंकि वह पंजाब में अकालियों को मिल रहा थोड़ा-बहुत समर्थन गँवाना नहीं चाहता।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग एक से अधिक कई मौकों पर अकाली दल के दोहरे मापदण्डों को देख चुके हैं जिनमें हाल ही का सी.ए.ए. का मामला भी शामिल है। उन्हों इस संवेदनशील मुद्दे पर सुखबीर बादल को दोबारा यह पूछा कि वह रा%य और किसानों की तरफ हैं या नहीं। उन्होंने कहा, ''क्या वह किसानों के हक में स्टैंड लेंगे? क्या वह यह सोचते हैं कि कृषि के विषय पर केंद्र फैसले ले सकता है?'' कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सुखबीर को पंजाब के लोगों के हित में एक बार सैद्धांतिक तौर पर पक्ष लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल की ही बैठक में यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकार द्वारा तीन साल पहले लिए गए फैसले सिर्फ फूड प्रोसैसिंग उद्योगों से सम्बन्धित कृषि मंडीकरण के फैसले लिए गए थे जिनके बारे में अकाली दल गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में राज्य सरकार प्रांतीय विषय के मामले में इस क्षेत्र की भलाई के लिए कोई भी फैसला ले सकती है परन्तु केंद्र सरकार को इन शक्तियों को छीनने का कोई अधिकार नहीं है जो यह ऑर्डीनैंस जारी किये गए हैं।

बादल परिवार ने पंजाब विरोधी ऑर्डीनैंसों की हिमायत करके पंजाबियों के साथ गद्दारी की

शिरोमणि अकाली दल अपनी विचारधारा छोड़कर भाजपा का चापलूस बना

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि बादल परिवार ने पंजाब खासकर किसानी के लिए बहुत ही हानीकारक सिद्ध होने वाले ऑर्डीनैंसों की हिमायत करके राज्य और किसानों के हितों के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए यह ऑर्डीनैंस जहाँ राज्यों के अधिकारों का हनन करते हैं वहीं इनके लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की यकीनी खरीद वाली चल रही मंडीकरण व्यवस्था के खात्मे का भी आधार बंधेगा।

श्री सिद्धू ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल को यह भली भाँति ज्ञात है कि इन ऑर्डीनैंसों से राज्य और यहाँ के किसानों की आर्थिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, परन्तु वह सिर्फ एक मंत्रालय के लालच में राज्य के किसानों को पीठ दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों को मिले अधिकारों को दबाने वाले केंद्र के इस फैसले की हिमायत करके सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के इतिहास को भी दागदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कृषि का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण कृषि सम्बन्धी यह ऑर्डीनैंस जारी करके मोदी सरकार ने भारत के संविधान और इसकी मूल भावना का उल्लंघन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अकाली दल की मौजूदा लीडरशिप ने राज्यों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के अपने पुराने एजंडे को तिलांजलि देकर मोदी सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों को चोट पहुंचाने वाले फैसलों की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि अकाली दल ने जम्मू-कश्मीर राज्य को तोड़कर तीन केंद्रीय प्रबंध वाले क्षेत्रों में बदलने के फैसले की भी हिमायत की थी। इन फैसलों से स्पष्ट है कि शिरोमणि अकाली दल की अपनी कोई विचारधारा नहीं है और यह अब पूरी भाजपा का चापलूस बनकर रह गया है। श्री सिद्धू ने कहा कि बादल परिवार ने मोदी सरकार में अपने मंत्रालय को कायम रखने को प्राथमिकता देकर यह सिद्ध कर दिया है कि यह परिवार राज सत्ता के बिना जी ही नहीं सकता फिर चाहे इसके लिए उसे पूरे पंजाब के हित भी क्यों न कुर्बान करने पड़ें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि इन पंजाब और किसान विरोधी ऑर्डीनैंसों को रद्द करवाने की मुहिम शुरु करके कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हमेशा की तरह पंजाब के सच्चे सपूत होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह, एक नहीं, कई बारी अपना राजसी भविष्य दाव पर लगाकर पंजाब के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। श्री सिद्धू ने कहा कि पंजाब पर थोपे गए पानी के समझौतों को पार्टी विचारधारा से उलट जाकर रद्द करना ऐसे ऐतिहासिक कदम हैं जिनके चलते कैप्टन अमरिन्दर सिंह आज हर पंजाबी के दिल में बसे हुए हैं।

कोरोना पर जीत के लिए लोगों का सहयोग निर्णायक - धर्मसोत

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि कोरोना पर जीत के लिए लोगों का सहयोग निर्णायक है और लोगों के सहयोग से ही इस असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है।

आज यहाँ यह खुलासा करते हुए स. धर्मसोत ने कहा कि कोरोना का खतरा फिलहाल टला नहीं है, इसलिए कोविड 19 पर फतह हासिल करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी किये निर्देशों का भविष्य में भी पालन करना बेहद जरूरी है। स. धर्मसोत ने कहा कि आज यदि पंजाब में कोरोना की फैलाव दर कम है तो इसका कारण राज्य सरकार की हिदायतों के पालन के लिए लोगों की तरफ से दिया गया भरपूर सहयोग एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से तालाबन्दी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को राशन बाँटने के अलावा स्वास्थ्य प्रबंधों को भी बड़े स्तर पर मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि समूचे भारत में पंजाब की कोरोना के साथ के मुकाबले में सम्बन्धित नीति को दूसरे राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है, जोकि पंजाब सरकार की सर्वोत्तम प्रदार्शन पर मोहर लगाता है।

स. धर्मसोत ने कोविड 19 के दौरान राज्यभर से आगे आए दानी सज्जनों और समाज सेवीं संस्थाओं की प्रशंसा करते हए कहा कि उन्होंने संकट की इस घड़ी में मानवता के कल्याण के लिए बहुमूल्य काम किया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने तालाबन्दी के दौरान सुचारू ढंग के साथ जरूरतमन्दों तक हर जरूरी मदद पहुँचाई, जोकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि दानी सज्जनों और समाज सेवीं संस्थाओं ने पूरी लगन और मेहनत के साथ राज्य सरकार का सहयोग किया है, जिससे राहत कार्यों में भारी मदद मिली है। स. धर्मसोत ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड 19 से सुरक्षित रहने के लिए किसी भी चीज को छूने के बाद हाथ जरूर धोएं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर हाथों को साबुन और पानी के साथ धोएं या सैनेटाईज करें, घर से बाहर जाते समय मास्क के साथ मुँह और नाक को ढकें और एक -दूसरे से दूरी बनाकर रखने से कोरोना से बचा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह बचाव का ढंग अपनाकर हम जहाँ अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, वहीं कोरोना का सामाजिक फैलाव भी रोक सकते हैं।

पंजाब सरकार द्वारा चुने गए 19 और मुख्य अध्यापकों को स्टेशन अलॉट

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने शिक्षा विभाग (सै. शि.) में चुने गए 19 और मुख्य अध्यापकों को स्टेशन अलॉट कर दिए हैं। इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि डायरैक्टर स्कूल शिक्षा श्री मुहम्मद तैयब ने इस सम्बन्धी आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रवक्ता के अनुसार शिक्षा विभाग (सै. शि.) में 672 मुख्य अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए जनवरी 2020 में चयन किया गया था। इन मुख्य अध्यापकों को पंजाब ऐजूकशन (स्कूल और इंस्पैक्शन) ग्रुप-बी सर्विस रूल्ज 2018और पंजाब ऐजूकशन सर्विस (स्कूल और इंस्पैक्शन बॉर्डर ऐरिया) ग्रुप-बी सर्विस रूल्ज 2018अधीन चुना गया था। इनमें से कुछ को 18जून 2020 को मुख्य अध्यापक की नियुक्ति के लिए पेशकश की गई। इनमें 19 ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया जिसके बाद इनको स्टेशन अलॉट कर दिए गए हैं।

न्यूज

बिहार विधान परिषद चुनाव में तारिक नहीं समीर होंगे कांग्रेस उम्मीदवार

पटना, (एजेंसी)। बिहार विधान परिषद के विधानसभा क्षेत्र से हो रहे चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन गुरुवार को कांग्रेस ने अपने कोटे की एकमात्र सीट पर घोषित उम्मीदवार तारिक अनवर की जगह अब समीर कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अपने कोटे की एकमात्र सीट के लिए बुधवार की रात पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की थी। नामांकन-पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन गुरुवार को श्री अनवर की जगह प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया गया। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि श्री अनवर का नाम और पता दिल्ली का होने के कारण वह नामांकन नहीं कर सके।

ईरान में फंसे तमिलनाडु के 700 मछुआरे वापस लौटेंगे : जयकुमार

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मत्स्य मंत्री डी जयकुमार ने गुरुवार को कहा कि ईरान में फंसे तमिलनाडु के 700 मछुआरों के जहाज से राज्य में लौटने का प्रबंध कर लिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों के मछुआरे ईरान में अनुबंध पर मछली पकड़ने के कार्य के लिए गए थे और लॉकडाउन के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगने से वे वहीं फंस गए। केंद्र और राज्य सरकार ईरान में फंसे मछुआरों को वापस लाने कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ई के पलानीसामी ने ईरान में फंसे मछुआरों की वापसी का प्रबंध करने का केंद्र से आग्रह करते हुए पत्र लिखा था, जिसक बाद ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारी मछुआरे से मिले और उन्हें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनकी स्वास्थ्य की जांच कराई।

पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम के विरोध में राजद ने निकाला साइकिल मार्च

पटना, (एजेंसी)। बिहार की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में हुई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में गुरुवार को साइकिल मार्च निकाला। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके बड़े भाई विधायक तेजप्रताप यादव के नेतृत्व में राजद के विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास से मार्च निकाला। मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ राजधानी की हृदयस्थली डाकबंगला चौराहा तक गया। इस दौरान समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि जब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी नहीं आएगी, तब तक पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों से किसान और कारोबारी भी परेशान हैं।

भारत में अब प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी रॉकेट और सैटेलाइट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में अब प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट और सैटेलाइट बना सकती है। यहां तक कि इसरो के मिशन में भी शामिल हो सकती है। इसरो प्रमुख के सिवन ने गुरुवार को कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में बड़ा सुधार करते हुए निजी क्षेत्र को अब रॉकेट एवं उपग्रह बनाने और प्रक्षेपण सेवाएं मुहैया कराने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने इसे बड़ा सुधार करार देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतरग्रहीय मिशन का भी हिस्सा बन सकता है।

इसरो के मिशन में भी हो सकती हैं शामिल

कैबिनेट ने ग्रहों पर अन्वेषण मिशन समेत अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बुधवार को अनुमति दी। सिवन ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निजी क्षेत्र रॉकेट, उपग्रह बनाने और वाणिज्यिक आधार पर प्रक्षेपण सेवाएं मुहैया कराने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र इसरो के अंतरग्रहीय मिशनों का हिस्सा हो सकता है। अवसरों की घोषणा के जरिए

ऐसा करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि सिवन ने कहा कि इसरो की गतिविधियां कम नहीं होंगी और वह उन्नत शोध एवं विकास, अंतरग्रहीय और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों समेत अंतरिक्ष आधारित गतिविधियां जारी रखेगा।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण (इन-स्पेस) केंद्र गठित

उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति देने और उनके नियमन के संबंध में स्वतंत्र फैलने लेने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण (इन-स्पेस) केंद्र का गठन किया गया है। सिवन ने कहा कि इससे न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाने में भी सहायता मिलेगी।

निजी कंपनियां अंतरिक्ष विभाग को दे सकती हैं आवेदन

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विभाग में यह बड़ा सुधार होने जा रहा है। तकनीकी, कानूनी सुरक्षा, गतिविधि संवर्धन के साथ-साथ निगरानी के लिए इन-स्पेस के अपने निदेशालय होंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। इन-स्पेस मंडल में सरकारी सदस्यों के अलावा उद्योग एवं शिक्षा जगत के सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को आकार लेने में छह माह का समय लगेगा, लेकिन निजी कंपनियां अंतरिम समय में अंतरिक्ष विभाग को अपने आवेदन दे सकती हैं। सिवन ने कहा कि निजी कंपनियां इन-स्पेस को सीधे आवेदन भेज सकती हैं, जो आवेदन का स्वतंत्र रूप से आकलन करेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) अंतरिक्ष गतिविधियों को आपूर्ति संचालित मॉडल से मांग संचालित मॉडल में बदलकर इस प्रयास में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे अंतरिक्ष संपदा का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

हुआवेई सहित 20 कंपनियों को चलाती है चीनी सेना, ट्रंप प्रशासन ने की लिस्ट तैयार

बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका

वॉशिंगटन ■ एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ऐसी 20 कंपनियों की लिस्ट तैयार की है, जिन पर या तो चीनी सेना का नियंत्रण है या चीनी सेना का स्वामित्व है। इसमें टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी हुआवेई और वीडियो सर्विलांस कंपनी हिकविजन शामिल है। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में शामिल कंपनियों पर अमेरिकी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है।

अमेरिका ने हुआवेई और हिकविजन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए पिछले साल ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था और सहयोगी देशों के साथ मुहिम चलाई थी कि हुआवेई को 5जी नेटवर्क से अलग रखा जाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (डीओडी) ने अमेरिका में कारोबार कर रही 20 ऐसी कंपनियों की लिस्ट तैयार की है, जिनको चीनी सेना का समर्थन प्राप्त है।

कंपनियों पर राष्ट्रपति लगा सकते हैं प्रतिबंध

कानून के मुताबिक पेंटागन की इस सूची में शामिल कंपनियों पर राष्ट्रपति प्रतिबंध लगा सकते हैं और इन कंपनियों की सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। हुआवेई, चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, एवीआईसी और वॉशिंगटन में चाइनीज दूतावास ने इस मुद्दे पर बोलने से इंकार किया है।

लिस्ट में विमान निर्माता कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑप चाइना भी शामिल

डीओडी के इस लिस्ट में चाइना मोबाइल कॉम्युनिकेशंस ग्रुप और चाइना टेलीकॉम कॉर्प, विमान निर्माता कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑप चाइना शामिल है। इसमें चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (सीआरआरसी), चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प भी शामिल है। सीआरआरसी पैसेंजर ट्रेन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1999 के एक कानून के तहत अमेरिका में कारोबार कर रही चीन की उनक कंपनियों सूचीबद्ध किया है, जिनका नियंत्रण या स्वामित्व पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के पास है।

हिकविजन ने आरोपों को बताया आधारहीन

हिकविजन ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा कि यह चाइनीज सेना की कंपनी नहीं है और ना ही कंपनी ने कभी सेना के लिए कोई रिसर्च या डिवेलपमेंट किया है। कंपनी ने कहा कि वह मुद्दे के समाधान के लिए अमेरिकी सरकार से बात करेगी। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी की दोनों राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने पेंटागन पर इस लिस्ट को प्रकाशित करने का दबाव बढ़ा दिया है। सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। वॉइट हाउस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ेगा तनाव

माना जा रहा है कि इस लिस्ट से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और अधिक बढ़ेगा। इससे पहले ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस महामारी को लेकर दोनों देशों में टकराव रहा है। हांगकांग को लेकर अमेरिकी रुख से भी चीन परेशान है। चाइना में उइगर मुस्लिमों पर जुल्म को लेकर चाइनीज अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले एक आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दस्तखत किया तो ड्रैगन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी।

दिल्ली में मरीज को कोविड सेंटर नहीं जाना होगा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसल से पीछे हट गए हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती पांच दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य ही होगा।

गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) की बैठक में इस बात का फैसला लिया है। यानी कि दिल्ली में अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे कोविड केयर सेंटर जा कर अपनी जांच नहीं करानी होगी। बल्कि पुराने सिस्टम के तहत सरकार और प्रशासन के लोग घर आकर क्लीनिकल एसेसमेंट और फिजिकल एसेसमेंट करके देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या नहीं।

बैठक में तय हुआ है कि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव के घर पर होम आइसोलेशन में रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई मरीज अपने घर में ही होम आइसोलेशन का पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार है, उसे ऐसा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो उसे कोविड केयर सेंटर में रहना जरूरी नहीं होगा।

उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल के बीच तकरार

पिछले हफ्ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से तकरार देखने को मिली थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि एलजी साहब के आदेश की वजह से एंबुलेंस का सिस्टम दबाव में है। बसों में लोगों को बैठा कर ले जाना पड़ रहा है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.